प्रेस रिलीज़

दिनांक: 05-04-2018

दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस के कार्यान्वयन पर सभी हितधारकों की हुयी बैठक

दिल्ली/एनसीआर : दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना, दिल्ली-एनसीआर की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं | विभिन्न परिवहन माध्यम से जहाँ दिल्ली से मेरठ जाने में लोगों को कई घंटे लग जाते हैं, वहीं यह परियोजना दिल्ली और मेरठ के बीच की यात्रा को 60 मिनट से भी कम कर देगी | साथ ही कॉरिडोर के आस-पास के क्षेत्र का तेज़ी से विकास भी होगा | इस बात को आप आरआरटीएस के स्लोगन से भी समझ सकते हैं – गति से प्रगति |

मेरठ के संभागीय आयुक्त ने आज अपने कार्यालय में दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में,सम्बंधित सभी हितधारकों की बैठक बुलाई | बैठक में सार्वजनिक प्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के अधिकारीयों तथा प्राधिकारियों जैसे वन, सिंचाई, जीडीए, एमडीए, पीवीवीएनएल आदि,मीडिया प्रतिनिधि एवं अन्य लोगों ने भाग लिया |

बैठक के दौरान, एनसीआरटीसी के अधिकारियों ने विशेष रूप से आरआरटीएस के बारे में बताया और आरआरटीएस के दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर के बारे में एक प्रस्तुति दी गयी । स्कीम, योजना एवं नागरिकों को परियोजना का परिवर्तनकारी लाभ और क्षेत्र के संतुलित और सतत आर्थिक विकास में परियोजना की भूमिका पर प्रकाश डाला गया | उन्होंने विस्तृत रूप से यह भी बताया कि आरआरटीएस एनसीआर में कार्यान्वित होने के बाद बहुत तेज़ और निर्बाध मल्टीमॉडल इंटरकनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जो आस-पास के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देगा । यह परियोजना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और अन्य रोजगार को प्रोत्साहित करेगा, तथा नए बाजारों और नए अवसरों को भी खोल देगा | क्षेत्र में प्रभावी ढंग से प्रदूषण और भीड़ को कम करने में भी फायदेमंद होगा।

परियोजना के चल रहे विकास के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए, एमडी / एनसीआरटीसी ने बताया कि पूर्व निर्माण गतिविधियों को लगभग पूरा कर लिया गया है, यूटिलिटी डायवर्जिंग,

सड़क चौड़ाई आदि के लिए निविदाएं अंतिम रूप ले रही हैं, प्रथम चरण (16.5 किमी) के सिविल निर्माण के लिए बोलियों को पहले से ही आमंत्रित किया गया था और एनसीआरटीसी पूरी तरह से जल्द ही निर्माण गतिविधियों को शुरू करने के लिए तैयार है|

आरआरटीएस कॉरिडोर में मेरठ मेट्रो नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर (परतापुर से मोदीपुरम) को मर्ज करने की योजना को विस्तार से समझाया गया । यह योजना आरआरटीएस नेटवर्क पर ही मेट्रो सेवा को मोदीपुरम और परतापुर के बीच चलाने की अनुमति देगा। एवं यह योजना इंटरचेंज को कम भी करेगी, यात्रियों के अनुभव को बढ़ाने और सार्वजनिक धन के 6,300 करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत करेगी। यह कार्य मेरठ के आरआरटीएस कॉरीडोर पर छ: अतिरिक्त स्टेशन जोड़कर किया जाएगा, जो परतापुर, रिठानी, ब्रह्मपुरी, भैसाली, एमइएस कॉलोनी और दौरली हैं |

उपस्थित लोगों ने पहल का स्वागत किया और कहा कि इसके माध्यम से, मेरठ के लोग अगले 4-5 वर्षों में एक व्यापक मोबिलिटी समाधान प्राप्त करेंगे, जो अभी भी लंदन के लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है।

हस्तिनापुर माननीय विधायक श्री दिनेश खटिक ने अन्य सार्वजनिक प्रतिनिधियों के साथ मेरठ को इस तरह के एक परिवर्तनकारी परियोजना लाने में भारत सरकार और भारत सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए अधिकारियों से आग्रह किया कि समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करें।

एमडी / एनसीआरटीसी ने क्षेत्र में कुशल मोबिलिटी समाधान प्रदान करने के लिए एनसीआरटीसी की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ उन्होंने आश्वासन दिया कि एनसीआरटीसी पेशेवर , सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्माण के दौरान सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय विधियों को अपनायेंगे।

परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई और विभागीय आयुक्त ने सभी विभागों और अधिकारियों को सलाह दी कि वे आवश्यक मंजूरी और अनुमोदन में तेजी लाएं और आरआरटीएस परियोजना

को पूरा करने करने के लिए सभी बाधाओं को दूर करें, जो कि यह परियोजना यूपी सरकार की प्राथमिकता है तथा यह आस पास के क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभदायक होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम (एनसीआरटीएस), जो कि केंद्र सरकार और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों का संयुक्त उद्यम है, पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर तीन क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर - दिल्ली-अलवर, दिल्ली-मेरठ और दिल्ली-पानीपत को कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) द्वारा तैयार किए गए इस तरह के कॉरिडोर को एकीकृत परिवहन योजना 2032 के तहत पहचाना गया है।